जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की हो सीबीआई जांच

कांग्रेस की मांग, मंत्री के खिलाफ हो कार्रवाई

भोपाल, 26 जुलाई. विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शनिवार को जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार को घेरा. कटारे ने कहा कि प्रदेश के गांवों में हर-घर जल पहुंचाने के लिए संचालित जल जीवन मिशन राजनेता, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ का शिकार हो गया है. इसमें 10,000 करोड़ का सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ है.

कटारे ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण मिशन का नाम बदलकर जल्दी-जल्दी-मनी मिशन बना दिया है. इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि पूर्व प्रमुख अभियंता समेत कार्यपालन यंत्रियों और रेट रिवाइज करने वाले अफसरों के साथ विभागों के प्रमुख सचिवों, मंत्री स्टाफ पर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए. कटारे ने कहा कि मुख्यमंत्री नल जल योजना पहले से ही फेल थी, लेकिन जल्दी मनी डकारने जल जीवन मिशन को भी लूट खसोट की स्थिति में ला दिया गया. उन्होंने कहा कि पीएचई के प्रमुख अभियंता कार्यालय के नोडल अधिकारी आलोक अग्रवाल ने ई-मेल से प्रदेश के सभी जिलों को एक मॉडल डीपीआर का प्रारूप भेजकर निर्देशित किया कि वह इसमें आंकड़े फीड कर भेज दें. उसी के अनुरूप क्रियान्वयन हुआ, जबकि वास्तविक डीपीआर फील्ड से बनानी थी. कटारे ने आरोप लगाया कि मिशन में स्थिति यह रही कि जिस अधिकारी को जितना फण्ड चाहिए, वह आलोक अग्रवाल व महेन्द्र खरे से बात कर एक प्रतिशत कमीशन पहुंचा देता और इसके बाद ये सीधे प्रमुख अभियंता से उसी दिन फंड जारी करा देते थे. कटारे ने कहा कि पीएचई के पूर्व प्रमुख अभियंता केके सोनगरिया, आलोक अग्रवाल व महेंद्र खरे के मोबाइल की सीडीआर, रिकार्डिंग की जांच से खुलासा हो जाएगा.

4 हजार का लोनिजर यंत्र 1 लाख में खरीदा

योजना में सिल्वर लोनिजर नाम का इंस्ट्रूमेंट खरीदने में घपला किया है. नोडल अधिकारी के मौखिक निर्देश पर 4 हजार रुपए का यह यंत्र 70,000 से 1 लाख रुपए तक में खरीदा गया है जबकि आईआईटी चेन्नई की रिपोर्ट अनुसार इस यंत्र की कोई उपयोगिता नहीं थी. पुरानी पाइप लाइन बिछाकर नए बिल लगा दिए गए जिसका खुलासा सीआईपीईटी की रिपोर्ट से हुआ, जिसमें बताया कि ठेकेदारों ने थर्ड पार्टी टेस्टिंग तो कराई लेकिन हकीकत में माल उठाया ही नहीं गया. नई साजिश के अंतर्गत पैसा खत्म होने पर ठेकेदारों से एक प्रतिशत राशि लेकर पुराने टेंडरों को रिवाइज्ड कर सभी जिले के टेंडरों में वृद्धि की गई. विभाग की मंत्री के प्रभार के जिले सिंगरौली में 265 प्रतिशत, सिवनी में 117, शिवपुरी में 184 प्रतिशत तक रेट रिवाइज हुए. इस तरह 15 से अधिक जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. इससे 2750 करोड़ की अतिरिक्त राशि का खर्च सरकार को उठाना पड़ा. मेन्युअल अनुसार टेंडर में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर नई टेंडर प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर पुराने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया.

अब मेडिकल स्टोर नहीं लगा सकेंगे डिस्काउंट का बोर्ड

डिस्काउंट से होती थी नकली दवाओं की सप्लाई

भोपाल, 26 जुलाई. मध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान पर डिस्काउंट के बोर्ड नहीं लगा सकेंगे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस तरह का प्रचार नहीं कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने इस मामले में प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं और इस अवैध टैक्टिस को 15 दिन में पूरी तरह खत्म करने की चेतावनी दी है. एमपीपीसी ने नोटिस जारी कर कहा कि कई मेडिकल स्टोर बोर्ड और सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट का लालच देकर उपभोक्ताओं को प्रभावित रहे हैं, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अनुसार अनैतिक और अवैध है। ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाने पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड किया जाएगा। साथ ही मेडिकल स्टोर पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

काउंसिल के नोटिस में यह भी कहा गया है कि बड़े कारोबारी अपनी आर्थिक ताकत के दम पर इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेकर छोटे मेडिकल दुकानदारों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है.

खाद की कमी से लाखों किसान हलाकान : सिंह

खाद वितरण की पारदर्शी व्यवस्था जरूरी

भोपाल 26 जुलाई. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में इस साल फिर खाद का संकट गहरा गया है. प्रदेश में खाद वितरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की सख्त जरूरत है 7 किसान हलाकान हो रहे हैं. प्रदेश को इस साल जरूरत से आधी मात्रा में खाद अभी तक आवंटित हुई है.

किसानों में खाद लेने के लिए मारा मारी मची हुई है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार को पत्र लिखने में समय जाया न करें बल्कि व्यक्तिगत रूचि लेकर स्वयं दिल्ली जाकर या फोन पर केन्द्र सरकार से बात करें. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश के ही हैं तो फिर क्या दिक्कत है? प्रदेश में खाद की किल्लत क्यों हो रही है? अजय सिंह ने मुख्यमंत्री को सचेत करते हुए कहा कि किसानों का आक्रोश बढ़े उसके पहले ही खाद की पर्याप्त व्यवस्था करवायें अन्यथा अप्रिय स्थिति निर्मित होने में देर नहीं लगेगी. उन्होंने कहा कि प्रायवेट दुकान वाले वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाकर आपदा में अवसर तलाश रहे है. यूरिया की काला बाजारी हो रही है और ब्लैक में दोगुने दामों पर बिक रही है. उसी किसान को यूरिया मिल रही है जो न चाहते हुए भी नैनो यूरिया की बोतल खरीद रहा है. डीएपी की जगह एनपीए लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जबकि इस वक्त मक्का और धान के लिए यूरिया की सख्त जरूरत है.

सिंह ने कहा कि दो बोरी यूरिया के लिए भी किसान केन्द्रों पर रात काट रहे है. कई दिन चक्कर काटने के बाद भी आवश्यकता से कम यूरिया मिल रहा है. कुछ ही किसानों को प्राइवेट दुकानो से खाद लेने के लिए टोकन दिये जा रहे है और बाकी आधे से ज्यादा किसान मायूस होकर लौट रहे है. उन्होंने कहा कि अमानक बीज के मामले भी सामने आए है जो बोनी के बाद अंकुरित ही नहीं हुए. ताजा उदाहरण देवास के खातेगांव का है. यहां कोलारी गांव के आठ किसानों ने 25 क्विंटल सोयाबीन बीज 6900 के भाव खरीदा जो आज तक अंकुरित नहीं हुआ. सीहोर जिले के 18 गांवों में बीजोपचार पावडर खरीद कर बोनी की गई लेकिन पूरी फसल खराब हो गई. सतना में बायर कंपनी का डुप्लीकेट फँगीसाइड बनाने का कारोबार पकड़ा गया है.

फुटपाथ पर टूटी पड़ी रैलिंग

भोपाल. वीआईपी रोड के फुटपाथ पर लगी रैलिंग को चोर काट ले गए. कुछ मौके पर छोड़कर भाग निकले. प्रशासन को भनक तक नहीं लगी.

रसोइया बहनों को 3 माह से नहीं मिला मानदेय-राशन

महिला स्व सहायता समूह महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल, 26 जुलाई. प्रदेश के शासकीय स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों और रसोइया बहनों को बीते तीन माह (मई से जुलाई 2025) से मानदेय और खाद्यान्न आपूर्ति नहीं मिली है. यह जानकारी संबंधित विभाग द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से सामने आई है, जिसने योजना के क्रियान्वयन में आ रही वित्तीय बाधा की पुष्टि की है.

25 जुलाई को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार से बजट की प्राप्ति न होने के कारण, स्व सहायता समूहों और रसोइया बहनों को भुगतान नहीं किया जा सका है. पत्र में आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, भुगतान की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी. शासकीय विद्यालयों में भोजन तैयार करने वाली रसोइया बहनों और भोजन प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे स्व सहायता समूहों की महिलाओं का कहना है कि लगातार तीन माह से बिना भुगतान के कार्य करना आसान नहीं है. कई स्थानों पर समूहों ने भोजन बनाने हेतु स्वयं की पूंजी लगाई है. प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा है. सरिता ओमप्रकाश सिंह बघेल का कहना है कि योजना से जुड़े लाखों परिवार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं और समय पर मानदेय न मिलना केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक स्तर पर भी चुनौती उत्पन्न कर रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस दौरान यह भी मांग की गई है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की अवस्थिति की पुनः समीक्षा की जाए. कई विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर बताई जा रही है. फिलहाल योजना से जुड़े समूह और प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उनका मानना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इससे योजना की गति और बच्चों के पोषण पर प्रभाव पड़ सकता है. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना राज्य में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक अहम प्रयास है.

चार दिन और आफत की बारिश, जनजीवन ठप

शहर की मुख्य सड़कें और कॉलोनियां पानी में डूबी

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 26 जुलाई. राजधानी भोपाल मे लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है.शुक्रवार रात से जारी बारिश के चलते शहर की कई मुख्य सड़के और कॉलोनियां पानी में डूबी नजर आ रही है, जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों का घरो से निकलना मुश्किल हो गया है,

वहीं कई निचले इलाकों में पानी घरों मे घुसने लगा है. सड़को पर भरे पानी से यातायात व्यवस्था

चरमरा गई है और कई वाहन खराब होकर बीच सड़क पर खड़े रह गए.

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान मे प्रदेश मे तीन ट्रफ, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक डिप्रेशन सक्रिय है जिससे प्रदेश मे भारी से अति भारी बारिश हो रही है. यह दौर अगले चार दिन तक जारी रहने का अनुमान है.मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने, गैर-जरूरी यात्रा से बचने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. आने वाले दिनों मे भोपाल सहित प्रदेशभर में मौसम का यही मिजाज रहने के आसार है.

अब तक कितनी बारिश

प्रदेश मे अब तक औसत 22.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 15.1 इंच बारिश होनी थी, इस हिसाब से 7.4 इंच बारिश ज्यादा हुई है, जो 49 प्रतिशत अधिक है. लगातार हो रही बारिश और जलभराव से शहर में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. जगह-जगह भरे गंदे पानी मे मच्छरो का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियो का खतरा मंडरा रहा है. नगर निगम की लापरवाही भी लोगो के गुस्से का कारण बन रही है.कई इलाकों मे नालियो की सफाई समय पर न होने से पानी की निकासी बाधित हो गई, जिससे जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है. लोगों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द नालियो की सफाई कर जलभराव की समस्या दूर करे.

राज्यमंत्री गौर ने साकेत नगर में किया पौधरोपण

भोपाल, 26 जुलाई. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने साकेत नगर में वार्ड क्र. 57 के साकेत नगर 2 स्थित शंकराचार्य पार्क में पार्षद सुरेन्द्र बाड़िका की उपस्थिति में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया. इस मौके पर स्थानीय रहवासियों ने भी पौधे रोपित किये. इस अवसर पर जोन अध्यक्ष नीरज सिंह, पार्षद अर्चना परमार, पूर्व पार्षद टीआर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे.

हावड़ा-भोपाल 15 और 17 सितंबर को निरस्त

भोपल, 26 जुलाई. भोपाल प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मण्डल में दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर प्री एनआई व एनआई का कार्य करने का निर्णय लिया गया है. पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के दौरान पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ और टर्मिनेट होने वाली हावड़ा भोपाल ट्रेन ट्रिप निरस्त रहेगी. उन्होंने जानकारी दी कि गाड़ी संख्या 13025 हावड़ा-भोपाल ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन हावड़ा से 15 सितंबर को और गाड़ी संख्या 13026 भोपाल-हावड़ा ट्रेन अपने प्रारम्भिक स्टेशन भोपाल से 17 सितम्बर 2025 को निरस्त रहेगी.

पश्चिम मध्य रेलवे दे रहा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 26 जुलाई. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल ने संवेदनशीलता का परिचय दिया. शनिवार को भोपाल मंडल के रेल सुरक्षा बल ने एक नाबालिग बालिका को उसके परिजनों से मिलाने की दिशा में प्रयास किया है.

यह पहल यात्रियों की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है. इटारसी स्टेशन पर सुरक्षा बालों को एक बालिका के परिजनों से बिछड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई. जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी से बालिका को उतारकर पूछताछ की. बालिका ने अपना नाम एवं पता बताते हुआ कहा कि यात्रा के दौरान वह अपने परिजनों से बिछड़ गई है. बालिका को महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में इटारसी के शासकीय चिकित्सालय ले जाकर आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. उसके बाद पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी गई. उनके निर्देश पर बालिका को मुस्कान संरक्षण गृह, इटारसी में सौंप दिया गया. इस बीच बालिका के परिजनों को सूचना देकर उन्हें त्वरित राहत प्रदान की.

नीलबड़ : सरकारी स्कूलों की हालात बदहाल

बच्चों को लेकर अभिभावकों में चिंता

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 26 जुलाई. राजधानी के नीलबड क्षेत्र वार्ड 26 स्थित शासकीय माध्यमिक शाला मे हालात दिनोंदिन खराब होती जा रही है. बारिश ने स्कूल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

खेल मैदान से लेकर कक्षाओं तक में पानी भरा है. मैदान कीचड़ और गंदे पानी से भर चुका है. जहां बच्चे मजबूरी मे खेलते है. कई कक्षाओं में सफाई की व्यवस्था नाम मात्र है. जगह-जगह गंदगी और सीलन है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पढ़ सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन वार्ड के पार्षद और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. नीलबड़ के ऐसे और भी स्कूल जिनकी हालत इससे भी खराब है. जैसे स्कूल में गंदा पानी कभी हटाया ही नही जाता, पीने का पानी नही है. स्कूल से आए दिन साँप निकलते है पर यहा की पार्षद और प्रशासन को कोई फरक नही पड़ता.

निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कमांडर प्रणय रावत का किया सम्मान

भोपाल, 26 जुलाई. निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कारगिल विजय दिवस पर सेना के कमांडर प्रणय रावत से बागसेवनिया स्थित उनके निवास पर उनका शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेटकर सम्मान किया. सूर्यवंशी ने कहा कि सेना के अदम्य शौर्य एवं साहस से भारतीय स्वयं को सदैव गौरवान्वित महसूस करते हैं.

लापरवाही बाइक सवार और ई रिक्शा चालकों के गिरने की रहती है आशंका

शहर की खस्ताहाल सड़कों से लोगों को सताने लगा डर

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 26 जुलाई. शहर भर की बारिश ने कहर बरसा रखा है तो वही दूसरी तरफ भोपाल की सड़कों ने लोगों के मन में डर बसा रखा है.

शहर भर की सड़कों में नेहरू नगर चौराहा, एमपी नगर ज्योति टॉकीज, न्यू मार्केट रोड, भोपाल स्टेशन सहित कई अन्य सड़कों की हालत अस्त व्यस्त है. कहीं छोटे गड्ढे हैं तो कहीं बड़े गड्ढे, कुछ जगह तो मेट्रो का काम चलने के कारण भी सड़कों पर किये गए गड्ढों को मिटटी से भर दिया गया है तो कई गिट्टी से बारे कही तो सूखे मसाले के घोल से बना दिया गया है तो कुछ को वैसे ही छोड़ दिया गया है जो कि बारिश और वाहनों की आवाजाही से और भी ख़राब हो गया है जिसके कारण कई बार बाइक सवार और ई रिक्शा चालकों के गिरने की समस्या बनी रहती है. नेहरू नगर चौराहे में भी सड़कों पर गड्ढे होने के कारण बाइक और स्कूटी सवार लोगों की गाड़ियां अक्सर गिरते-गिरते बचती हैं. स्थनीय निवासी अजय बताते हैं कि शाम होने के बाद चौराहे से नेहरू नगर पुलिस लाइन रोड पर व्यस्तता बढ़ जाती है, तब भारी वाहनों के साथ छोटे-बड़े वाहन भी खूब गुजरते हैं, पर कई बार इन गड्ढों के कारण छोटे वाहन चालकों को कई समस्यायों का सामना करना पड़ता है.

मेट्रो कार्य प्रगति से गड्ढों की नहीं हो रही भराई

शहर के कई क्षेत्रों में मेट्रो कार्य प्रगति पर है और इस बीच सड़क पर मेट्रो कार्य हेतु कई गड्ढे किये जा रहे है जिसमे से कुछ गड्ढों को मिटटी से भर दिया जा रहा है तो कुछ गड्ढों को कंक्रीट से आधा भरकर आधा छोड़ दिया जा रहा जिसकी वजह से भी सड़कों पर छोटे वाहनों के पलटने और दुर्घटना जैसे स्थिति आय दिन देखने को मिलती है. डिपो चौराह से टीटी नगर सड़क मार्ग पर ऐसे कई गड्ढे हैं जिनको आधा भरकर छोड़ दिया गया है. जिसकी वजह से प्रतिदिन मार्ग से गुजरने वाले लोगों को दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है.

ई-रिक्शा चालक फिर आंदोलन की राह पर

भोपाल. शहर में एक बार फिर ई-रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन हो सकता है. कई ई-रिक्शा चालक रणनीति बनाने में लगे हैं. वे जल्द ही अपनी मांगों को लेकर मुखर हो सकते हैं.बीते गुरुवार को भी शहर के जहांगीराबाद रोड से कलेक्टर ऑफिस तक ई-रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने नो-एंट्री क्षेत्रों में चलने की अनुमति, पार्किंग की सुविधा और वैकल्पिक मार्गों की मांग उठाई थी. वर्तमान में शहर में करीब 11,000 से ज्यादा ई-रिक्शा चालक हैं. अधिकांश का कहना है कि 12 प्रमुख वीआईपी सड़को पर ई-रिक्शा की नो-एंट्री के कारण उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है.